

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

के संस्कृति विद्यापीठ के अंतर्गत

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर दलित एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र

में एम.फिल. उपाधि हेतु प्रस्तुत

"दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ; एकअध्ययन"

(विशेष संदर्भ : वर्धा शहर, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र)

लघु शोध-प्रबंध

2013-2014



शोधार्थी

शोध निदेशक

सुश्री.निताचांगदेव देशभ्रतार

प्रो.डॉ.एल.कारुण्यकरा

एम.फिल.दलित एवं आदिवासी अध्ययन

अधिष्ठाता- संस्कृति विद्यापीठ,

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर दलित

निदेशक डॉ. बाबासाहब आंबेडकर

एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र

दलित एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट मानस मंदिर, गांधी हिल्स, वर्धा- 442005 (महाराष्ट्र) भारत

विषय - सूची

प्रमाण-पत्र	(i)
घोषणा-पत्र	(ii)
आभार	(iii)
अध्याय	पृष्ठ संख्या
1. प्रथम अध्याय :शोध प्रविधि का परिचय	1 - 17
2. द्वितीय अध्याय :दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ एवं यौन उत्पीड़न	18 - 63
3. तृतीय अध्याय :वर्धा शहर की दलित कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ; एक अध्ययन	64 - 90
4. चतुर्थ अध्याय-: वर्धा शहर की आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ; एक अध्ययन	91 - 110
5. पंचम अध्याय -: निष्कर्ष एवं सुझाव	111 - 116
परिशिष्ट	
• संदर्भ-ग्रंथ सूची	117 - 121
• प्रश्नावली	122 - 126
• छायाचित्र	127 - 128

प्रथम अध्याय

शोध प्रविधि का परिचय

1.1 प्रस्तावना

1.2 साहित्य पुनरावलोकन

1.3 शोध का उद्देश्य

1.4 शोध की परिकल्पना

1.5 शोध प्रविधि

1.6 अध्यायीकरण

1.7 परिशिष्ट

शोध प्रविधि का परिचय

1.1 प्रस्तावना

आज़ादी के 66 साल बीत चुके हैं। फिर भी हम स्वतंत्र भारत में रहकर समाजनिर्मित जातिव्यवस्था के अंतर्गत खुद को आज़ाद एवं सुरक्षित मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? देश अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो गया लेकिन भारतीय समाज का आधे से जादा हिस्सा वर्तमान में भी गुलामगिरी का जीवन यापन कर रहा है। यह उपेक्षित बहुजन समाज शोषित है, उत्पीड़ित है, अज्ञान में है, अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। और जातिगत वर्गव्यवस्था में झुलस रहा है। इस बहुजन वर्ग में दलित आदिवासी वर्ग का विशेषतः समावेश है। यह दलित आदिवासी वर्ग आज़ादी के पूर्व भी गुलाम था आज़ादी के पश्चात् भी गुलामी में ही जी रहा है। यह वर्ग हजारों साल पहले स्वतंत्र था। लेकिन भारत देश में परायण आर्यों ने आकर यहाँ के मूलनिवासीयों को हराया और यहाँ के मूल जिन्हें अनार्य संबोधित किया गया उन्हें अपना गुलाम बनाया। वर्तमान के दलित आदिवासियों ने उनकी गुलामी अस्वीकार की। लेकिन शेष वर्ग ने आर्यों का साथ दिया। तभी से आर्य और अनार्य का संघर्ष चालू है। आर्यों ने अनार्यों का शोषण और उत्पीड़न शुरू कर दिया। तभी से यही संस्कृति चली आ रही है।

आर्य जो आज सवर्ण कहलाते हैं, दलित और आदिवासी को कभी अपने समाज का अंग नहीं मानते। वे शुरू से ही उनपर वर्चस्व बनाये रखना चाहते हैं। उन्होंने इस दलित आदिवासी वर्ग को असंख्य यातनायें दीं। जिसमें बालक, बुजुर्ग, स्त्री-पुरुष सभी वर्ग थे। शुरू से ही उन्होंने दलित आदिवासीयों के अस्तित्व को नकारा। सवर्णों ने दलित आदिवासियों को अतिशूद्र का दर्जा दिया। उनके सभी कार्यों पर निर्बंध डाल दिये गये। उन्हें रूढ़ी-परंपरा और संस्कृति से जखड़ दिया। खुद के बनाये हुये अघोरी नीतिनियमों को उनपर थोप दिया गया। आज भारत 21 वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कई बहुजन समाज की उन्नति बाकी है। बहुजनों को छोड़ अन्य वर्ग का समाज प्रगतिपथ पर है। बहुजन समाज

को अभी भी अपनी उन्नति के लिये दुनिया भर की समस्याओं से झुलस ना पड़ रहा है। शासन प्रशासन सब खुली आँखों से देख आनंद उठा रही है। क्योंकि वहाँ पर भी सवर्णों का ही वर्चस्व है। यदि कोई दलित आदिवासी वर्ग अपने अधिकारों की माँग करता है या जुल्म के खिलाफ संघर्ष करता है उसे इसकी सजा भूगतनी पड़ती है।

भारत के संविधान निर्माण कर्ता बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर जी ने उपर्युक्त सभी समस्याओं का गहन अध्ययन कर संविधान में अनुच्छेद (15) के अंतर्गत किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करने का उल्लेख किया गया है। बाबासाहब खुद इन सब समस्याओं के भुक्तभोगी रह चुके हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में अंतिम समय तक सवर्णों के खिलाफ बहुजन समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। संविधान के रूप में बाबासाहब ने यह जीत हासिल भी की। और उसी आधार पर आज बहुजन समाज के बहुसंख्य लोगों ने अपनी उन्नति भी की। लेकिन दुःख की बात तो यह है की, 15 प्रतिशत समाज आज 85 प्रतिशत समाज पे अपनी एकता के आधार पर अभी भी जुल्म ढा रहा है। क्योंकि बाबासाहब का बहुजन समाज आज भी संघटित नहीं है। बाबासाहब ने अपने बहुजनों को उपदेश दिया था शिक्षित बनों, संघर्ष करो और संघटित रहो और संघर्ष करों। लेकिन आज भी बहुजन समाज बाबासाहब के उपदेशों पर कायम नहीं है और इस वजह से ही आज बहुजनों को असंख्य समस्याओं से झुलसना पड़ा रहा है। कुछ बाबासाहब के अनुयायी उनके बताये हुए मार्ग पर चल रहे हैं लेकिन उन्हें बहुजनों से जैसा चाहिये वैसा प्रतिसाद नहीं मिल पा रहा है और यह एक बड़ी शोकांतिका है।

वर्तमान में देश के कोने-कोने में फैले हुये दलित आदिवासी समाज पर शोषण और उत्पीड़न की हजारों घटनायें घट रही है। हर तरफ उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। दिनों-दिन यह समस्यायें खत्म होने के बजाय अपनी सीमायें लाँघ रही है। लेकिन

फिर भी शासन और प्रशासन चुप है। कोई हरकत में नहीं आ रही है, आखिर क्यों? इस क्यों के पीछे का कारण सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है। लेकिन बहुसंख्य समाज जो अभी भी अशिक्षित है, बाबासाहब के विचारों से अनभिज्ञ है और खुद को गुलामीयों से मुक्त ही नहीं कराना चाहता है, वे इसका परिणाम भूगत रहे हैं और अपने आनेवाली पीढ़ियों के लिये समस्याओं का निर्माण कर रहे हैं। यह लोग आज भी संविधान को नहीं जानते। संघटित नहीं है। अपने मौलिक अधिकारों से अनभिज्ञ है। उसके प्रति सजग नहीं है। इसलिए वे इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। बाबासाहब ने कहा है, "गुलामों को जाति की गुलामी का एहसास करा दो, वे गुलामी (जाति) की जंजीर खुद तोड़ देंगे। तभी सभी बुद्धिमान बन सकते हैं।" फिर भी बहुजन लोग इतिहास को भूल कर फिरसे इतिहास को दौराने की गलती कर रहा है। सोचने वाली बात है, अगर उस वक्त बाबासाहने अपने अंतिम साँस तक सवर्णों से दलित आदिवासी और अन्य पिछड़ी समाज के अधिकारों के लिये संघर्ष नहीं किया होता तो आज क्या स्थिति होती? लेकिन आज भी बहुजन समाज सो रहा है। वे इतिहास भूल गये (कुछ अपवाद छोड़) बाबासाहब के विचारों को भूल गये। परिणामतः आज भी दलित आदिवासी और अन्य पिछड़ा समाज अनगिनत समस्याओं से घिरा हुआ है।

भारत देश जहाँ राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ऐसे कहीं राज्य है। आर्ये दिन इन सभी राज्यों में दलित आदिवासियों का उत्पीड़न बड़ी तादाद में हो रहा है। खुले आम स्त्रियों पर अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं। इसमें मासूम कलियों का समावेश है। इन स्त्रीयों में घरगुती महिलायें, श्रमिक महिलायें तथा कामकाजी महिलायें जो अच्छेओहदे पर हैं, साथ ही मासूम बच्चीयाँ जो स्कूल पढ़ती हैं या घर पर रहती हो, और वृद्ध महिलाओं का भी समावेश है। यह आज वर्तमान स्थिति में अत्यंत अमानवीय घटना है। आर्ये दिन मीडिया, समाचार-पत्र, पत्रिकायें इनमें यह खबरें बड़ी तादाद में प्रकाशित हो रही हैं। यह तो दलित आदिवासी महिला की बात है लेकिन दलित आदिवासी पुरुष भी सवर्णों द्वारा अत्याचार के बली पड़ रहे हैं। उनका भी हर प्रकार का शोषण किया जा रहा है।

इसप्रकार आज देश के कोने कोने से दलित आदिवासीयों चीखें सुनायी दे रही है। लेकिन फिर भी प्रशासन अनभिज्ञ जैसा बर्ताव कर रही है। एस. सी.,एस. टी. कमिश्नर के अनुसार तो रोज हजारों घटनायें घड़ती है लेकिन कुछ ही मामले सामने आते है। कुछ मामलें दर्ज होते है, कुछ दर्ज ही नहीं करवाते। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर दलित आदिवासी समाज पर अत्याचार नहीं होते होंगे। घर से बाहर, स्कूल से लेकर केंद्रिय विश्वविद्यालय, कस्बे से लेकर शहर, खोतीहर, श्रमिक से लेकर उच्चपद पदस्थ कर्मचारी, सरकारी गैरसरकारी संस्थायें, पुलिस थाना, हॉस्पिटल हर जगह शोषण के मामले सामने आ रहे है।

भारत की राजधानी, देश की तख्त समझने वाले दिल्ली में प्रभावी शासनकर्तो के बावजूद एक इंजिनियरींग महाविद्यालय में उँची जातियों के छात्रों द्वारा दलित छात्रों के शोषण का मामला सामने आया। आजादी के बाद भी यह शोषण का मामला मानवजाति को कलंकित करने वाला है।

दलित आदिवासियों का शोषण यह संविधान के निर्माण से कुछ हद तक खत्म हो गया था। लेकिन आज भी यह समस्यायें फिरसे अपना रौद्र रूप धारण कर रही है। देश में चारों ओर इन घटनाओं को 'आम' बना दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले स्वयंघोषित संत 'आसाराम बापू' 'संत' की उपाधि को ही कलंकित कर दिया। उनके द्वारा गुरुकुल की हजारों छात्राओं के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया। इन हजारो छात्राओं में कितने ही दलित आदिवासी शिष्या या छात्राओं का शोषण किया गया होगा। क्योंकि ऐसे आश्रमों में ज्यादा तर वही लोग अपनी बच्चीयों को भेजते है जो आर्थिक रूप से पिछडे है। ऐसे लोग दलित आदिवासी वर्ग में ही जादा है। महाराष्ट्र में स्थित एक केंद्रिय विश्वविद्यालय में एक अम्बेडकरवादी आदिवासी सहायक प्रोफेसर को फर्जी केस में फँसाकर उन्हें पद से निष्कासित किया गया। वैसे ही अन्य पिछडी जाति के एक युवक द्वारा एक आदिवासी छात्रा को छात्रवृत्ति से वंचित रखने पर आवाज उठायी तो उसे नौकरी से निकाला गया। कुछ दिनों पहले

वर्धा जिला (महाराष्ट्र) के एक देहांत में आदिवासीयों पर हिंदूओं द्वारा हमला किया गया/जिसमें एक आदिवासी वृद्धा-महिला की मृत्यु हो गयी। और अन्य लोग बुरी तरह जखमी हो गये।

बिहार राज्य में भी जातीय हिंसा बढ़ रही है। आर्ये दिन वहाँ के जमींदार जो सवर्ण हैं दलित वर्ग के खेत मजदूरों पर वर्चस्व दिखा कर उनका शोषण कर रहे हैं। किसी को मजदूरी नहीं मिल रही है तो किसी के भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसी अनेक वारदातें हो रही हैं।

सरकार द्वारा दलित आदिवासीयों के बच्चों को शैक्षिक सुविधा देने हेतु योजनायें आती रहती हैं। लेकिन समाज के शत्रु जो अभी भी दलित आदिवासीयों की उन्नति नहीं चाहते, इन योजनाओं से उन्हें वंचित रखते हैं। ऐसी अन्य योजनायें भी आती हैं, जिससे दलित आदिवासीयों का सर्वांगीण विकास हो, उन्नति हो, लेकिन उन्हें समाज के शत्रुओं द्वारा उन तक नहीं पहुँचाया जाता है।

शहरों से दूर अति दुर्गम भाग, जहाँ पर दलित आदिवासी लोग आज भी रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या आदिवासीयों की है। यह अति दुर्गम भाग सुख-सुविधाओं से कई दूर है। यहाँ पर ना शिक्षा की व्यवस्था रहती है, ना उपचार केन्द्र। इन लोगों को अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने हेतु आस-पास के ग्राम में जाना पड़ता है। दो वक्त की रोटी इनको नसीब नहीं होती। अन्य सुविधायें का तो सपना भी नहीं देख सकते यह लोग। फिर भी देश में सर्वत्र घोषित किया जाता है की भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा, सबको अन्न सुरक्षा मिलेगी, कोई भी भूखा नहीं रहेगा इत्यादी।

इसी दृष्टिकोण से आश्रम शालाओं का निर्माण किया गया है। जहाँपर दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्र के दलित आदिवासी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। हाल ही की घटना है, नागपूर जिले के पास में एक ग्राम के आश्रम शाला में आदिवासी लड़कियाँ जो शिक्षा हेतु वहाँ पर रहती हैं। उनका शिक्षक द्वारा शारीरिक शोषण का भयावह मामला सामने आया।

एक आदिवासी महिला पुलिस कर्मी अपने उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल हुयी तो वहीं पर कार्यरत कर्मचारीयों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ऐसी एक नहीं अनगिनत घटनायें देश के कोने-कोने घट रहीं हैं। लेकिन फिर भी ना सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठायें जाते हैं और नाही दलित आदिवासी समाज संघटित हो कर संघर्ष कर पा रहा है। कुछ लोग इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। क्या करें? देश की समाजव्यवस्था शुरू से ही शोषित एवं पीड़ितों के प्रति उदासीन रही है। जो सत्य है, जो अपनी एवं दूसरों के मौलिक अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करता है, उसे गलत ठहराया जाता है साथ ही उसे इसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। दूसरी तरफ का चित्र इसके विपरीत है, जो असत्य है, जो अपनी वैयक्तिक स्वार्थ हेतु दूसरो के अधिकारों को छिनता है उसे यहाँ सर आँखो पर बिठाया जाता है। साथ ही उसके गुणगान भी होते हैं। उसे समाज में अच्छा व्यक्तिमत्व होने का दर्जा भी प्राप्त होता है। फिर वह एक बलात्कारी हो निष्पाप लोगों की हत्या करनेवाला हो या फिर शोषण करने वाला।

आयें दिन देश में दलित आदिवासीयों के शोषण और उत्पीड़न के कई मामले सामने आ रहे हैं। उनमें से एक दलित आदिवासीयों महिलाओं के उत्पीड़न एवं शोषण का मामला दिनों दिन बढ़ रहा है। यह एक ज्वलंत और अत्यंत अशोभनीय बात है। दलित आदिवासी महिला हो या देश की कोई भी समाज की महिला हो, उसका शोषण एवं उत्पीड़न करना बड़ी निंदा की बात है। आज देश में सर्वत्र महिलाओं ने जो उन्नति की है, वह प्रशंसनीय है ओर गौरवपूर्ण भी। लेकिन इसमें भी दलित आदिवासी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। कुछ अपवाद छोड़ दिये बाकि सब दलित आदिवासी वर्ग की ही महिलायें शोषण एवं उत्पीड़न की बली चढ़ायी जा रही है। इनमें भी गरीब, अशिक्षित, श्रमिक और कामकाजी महिलायें सभी का शोषण हो रहा है। रोज की जिंदगी में इन महिलाओं में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

एक तरफ कहते हैं भारत देश आज 21 वीं सदी को ओर साथ ही उत्तर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सही तो यह है कि, देश इनके विपरीत कार्य कर रहा है। यहाँ पर ना व्यक्ति स्वतंत्रता की अहमियत है, नहीं मौलिक अधिकारों की। जिस देश में आज भी दलित आदिवासी वर्ग गुलामी में अपना जीवना यापन कर रहा है, वहाँ उत्तर आधुनिकता कैसी? आज दलित आदिवासी समाज देश का वह बहुजन समाज है जिसे हजारों सालों से उन्नति से दूर रखा गया है। यह समाज आज भी अपनी मौलिक अधिकारों से वंचित है। जिससे उसकी सर्वांगीण स्थिति प्रगतिपथ पर नहीं है। यह वर्ग आज सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, धार्मिक और राजनीतिक ऐसी कहीं समस्याओं झुलस रहा है। परिवार की आर्थिक परिस्थिति को सक्षम करने हेतु जब एक दलित आदिवासी महिला अर्थाजन करने बाहर निकलती है तो उसे भी अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थाजन करना, परिवार की आर्थिक परिस्थिति को सक्षम बनाना, क्या यह कोई गुनाह है? जब एक महिला पढ़ लिखकर सुशिक्षित होकर काम करती है, नौकरी करती और अपने साथ अपने परिवार को भी संभालती है, क्या यह भी कोई अपराध है? आज दलित आदिवासी महिलायें शिक्षित बन हर क्षेत्र में नौकरी कर रही हैं। आगे बढ़ रही हैं। यह बड़ी गर्व की बात है। लेकिन फिर भी वही बात आती है जातिव्यवस्था की, भेदभाव की। यहाँ पर भी यह महिलायें सुरक्षित नहीं हैं। जब सुशिक्षित कामकाजी महिलाओं के साथ शोषण, उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं तो अनपढ़, और श्रमिक महिलाओं की क्या स्थिति होगी। वे महिलायें तो अपने अधिकारों को भी नहीं जानती।

बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद (15) में स्त्री-पुरुष समानता का अधिकार दिया है, समाज धर्म, जाति, वर्ग का दर्ज दिया है फिर भी कार्यस्थलों पर महिलायें सुरक्षित नहीं हैं। गंभीरता से सोचे तो आज भी मानवीय अधिकारों का खुले आम उल्लंघन हो रहा है। यही उपर्युक्त सभी समस्याओं से स्पष्ट होता है। देखा जायें तो महिला उत्पीड़न की समस्यायें अति प्राचीन हैं। उस वक्त अज्ञानता, रूढ़ी-परंपरायें, संस्कृति आदि गुलामीयों के

जंजीरो ने महिलाओं को जखड़ लिया था। लेकिन वर्तमान में यह सब कहाँ तक उचित है। कहीं साहित्यकारों ने महिला उत्पीड़नों के बारे विश्लेषण लिखा है। उन्हें समाज के सामने लाने का प्रयास भी किया है। लेकिन फिर भी यह समस्यायें बढ़ रही हैं। आज के स्थिति में यह अध्ययन का विषय है। कामकाजी दलित आदिवासी कामकाजी, गृहीणी, श्रमीक, महिलाओं के साथ दिनों-दिन शोषण एवं उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। फिर से हो चाहे वह शोषण, उत्पीड़न घर में हो या घर के बाहर। सामान्यतः घर में कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण कम होता है जबकि बाहरी क्षेत्र में उत्पीड़न की समस्यायें अधिक प्रतिशत में पायी जाती हैं। क्योंकि बाहरी क्षेत्र होने कारण घर से बाहर अकेली महिला को असहाय, कमजोर समझकर उससे अनुचित व्यवहार किया जाता है।

इसलिए कामकाजी महिलायें सुशिक्षित होने के बावजूद भी कार्यस्थलों पर सुरक्षित नहीं है। वर्तमान में दलित आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का पुनः अध्ययन कर फुल तथ्यों की खोज करने का एक छोटा सा प्रयास प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध द्वारा किया जा रहा है।

मनुष्य प्राणी यह शुरू से ही अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने अपनी जंगली अवस्था से आज की स्थिति को प्राप्त किया है। अनगिनत खोज करके समाज को जटिल कर दिया है। शोध से ज्ञान में वृद्धि होती है। और इसी ज्ञानपिपासा को शांत करने के लिए मनुष्य खोज करना है और सत्य तक पहुँचता है। सत्य की खोज को वैज्ञानिकता के आधार पर जाँचता भी है। मनुष्य समाज की निर्मिती तो की है लेकिन उसे इतना जटिल बना दिया है की आज समाज में मनुष्य को अनागिनत समस्यायें निर्माण हो रही है। यह समस्यायें भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, अपराध, भ्रष्टाचार, शोषण, उत्पीड़न आदि समावेश है। समाज की कोई भी

समस्या सुलझाने के लिए शोध का अत्यंत महत्व है ओर शोध से समस्या का हल निकालने में सहायता होती है।

भारतीय संविधान में स्त्री-पुरुष, धर्म, जाति, के बारे में समसमान अधिकारों का प्रावधान दिया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में स्त्री-पुरुष, धर्म, जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सर्वत्र मानवीय अधिकारोंका उल्लंघन हो रहा है। समाजो शुरू से ही जिस दलित आदिवासी वर्ग का अस्तित्व नकारा है, उस वर्ग की महिलाओं पर दिनों-दिन अत्याचार बढ़ रहे। जो अत्यंत गंभीर समस्या है। साथ ही उनके अत्याचारों से कही महिलाओं की मृत्यु भी हो रही है। जिससे महिलाओं का प्रमाण भी घट रहा है। इनमें स्त्री भ्रुण हत्यायें भी हो रही है। जो निंदा की बात है। एक और कहीं ज्यादा निंदनीय वह बात है की, एक दलित आदिवासी स्त्री पढ़ लिखकर जब अर्थाजन के लिये बाहर जाती है तो वहाँ पर उसका शोषण किया जाता है। उसे शारीरिक, मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जिससे कामकाजी महिलाओं का आत्मविश्वास कम हो जाता है। मानसिक संतुलन बिघड़ता है। अन्य समस्यायें भी उत्पन्न होती है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में इसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 'दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ ; एक अध्ययन' (विशेष संदर्भ : वर्धा शहर, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र) विषय का चयन किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में दलित एवं आदिवासी महिलाओं का प्राचीन काल से हो रहे उत्पीड़न को विश्लेषण के साथ उत्पीड़न की अवधारणाओं को भी स्पष्ट किया जायेगा। वर्तमान में दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं को किस प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ रहा उनके साथ किस प्रकार शोषण एवं उत्पीड़न हो रहा है, तथा उनके साथ यौन उत्पीड़न की समस्याओं का भी विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत शोध में किया जाएगा। क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले एवं भारतीय नारी के उद्धार कर्ता बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर का नारी उत्थान में जो योगदान रहा है, उसका भी विवेचन जायेगा। वर्धा शहर में वर्तमान में

दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थलों पर निर्माण हो रही समस्याओं का विश्लेषण भी किया जायेगा। वर्धा शहर में विविध क्षेत्र में कार्यरत दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं को मिलकर उनके द्वारा संकलित तथ्यों को तथा महिलाओं के समस्याओं को रोकने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का विवेचन भी प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध में जायेगा।

1.2 साहित्य पुनर्वलोकन

प्राचीन काल से जुल्मों का शिकार होता आ रहा है दलित एवं आदिवासी वर्ग। उसमें भी एक दलित और आदिवासी महिला तो दोहरी शोषित है। इन दलित एवं आदिवासी वर्ग की महिलाओं की स्थिति को और भी दयनीय किया गया है। दलित आदिवासी महिला घर से ज्यादा बाहर के लोगों से पीड़ित है। कामकाजी महिलायें परिवार में आर्थिक स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन अपनी व्यावसायिक जीवन के कारण उन्हें घरेलू समस्याओं से ज्यादा बाहरी समस्याओं का शिकार होना पड़ता है। समस्या तो और भी बढ़ जाती है जब वह महिला किसी दलित या आदिवासी वर्ग की होती है।

इसी संदर्भ में कहीं सामाजिक सुधारकों ने, समाज वैज्ञानिकों ने, साहित्यकारों ने गहन और गंभीरता पूर्वक अध्ययन करके साहित्य का निर्माण किया है। शोधकर्ताओं ने भी इस विषय पर अनेक शोध प्रबंध प्रस्तुत किये हैं। इसी विषय पर निम्नलिखित साहित्यों का भी सहयोग है।

1) मोहनदास नैमिशराय संकलित एवं संपादित "दलित उत्पीड़न की परम्परा और वर्तमान" (2007) में देश के सभी राज्यों में हो रहे दलित उत्पीड़न के मामले, इतिहास राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हुई घटनाओं के विस्तृत विवरण के साथ विश्लेषण भी है। दलित महिला अधिकारी का यौन उत्पीड़न, महिला उपप्रधान का उत्पीड़न इत्यादी कामकाजी महिलाओं के

उत्पीड़न का भी विश्लेषण किया गया है। साथ ही अन्य दलित महिलायें, छात्र-छात्रायें इनके शोषण को भी विश्लेषण किया गया है।

2) डॉ. मंजू सुमन लिखित "दलित नारी : एक विमर्श" (2004) पुस्तक में उन्होंने समाज में उपेक्षित दलित आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में विवेचना की गयी है। तथा उनके स्थान और महत्व को भी विश्लेषित किया गया है।

3) डॉ. ज्ञान प्रकाश गौतम लिखित "दलित महिला सशक्तिकरण एवं वैश्वीकरण" (2011) में दलित नारी की समस्यायें एवं संघर्ष के बारे में तथा संवैधानिक अधिकारों के बारे में विवेचन किया गया है।

4) डॉ. मंजू लता लिखित "अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न" (2012) पुस्तक में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को विशद किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति की महिलाओं के उत्पीड़न के कारण, स्वरूप एवं उत्पीड़न के प्रभावों को विस्तृत रूप में विशद किया है।

5) भास्कर मारोतराव नेवारे लिखित "आदिवासी गोवारी और संघर्षयुग" (2004) में लेखक ने आदिवासीयों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती को विश्लेषित किया है। साथ आदिवासी संस्कृति को भी विश्लेषित किया है। वर्तमान हो रहे आदिवासीयों की शोषण के बारे में तथा उनके मानवीय अधिकारों के उल्लंघन को भी विश्लेषित किया है।

6) के.आर.शहा. संपादित "आदिवासी सत्ता" पत्रिका में समस्त आदिवासी तथा आदिवासी महिलाओं की समस्याओं पर विश्लेषण किया गया है। देश में कोने कोने में आदिवासी महिलाओंपर जो अनपढ़ अशिक्षित, शिक्षित तथा सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसी महिलाओं; के यौन शोषण के बारे में कई घटनाओं का विश्लेषण किया है। यह

समस्त दलित आदिवासीयों की ज्वलंत समस्याओं को पत्रिका के माध्यम से देश के हर राज्य में प्रचार एवं प्रसार करने का प्रयास कर रही है।

1.3 शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं-

- 1) दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के बारे में अध्ययन करना।
- 2) वर्धा शहर की दलित कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करना।
- 3) वर्धा शहर की आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करना।

1.4 शोध की परिकल्पना

अध्ययन के उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु तथा संबंधित विषय के तथ्यों को खोजने के लिए संबंधित विषय के बारे में पूर्वज्ञान या अनुभव होना जरूरी है। और इन्हीं पूर्वज्ञान के आधार पर विषय से संबंधित कुछ सामान्य अनुमान लगाते हैं जिसे 'परिकल्पना' कहते हैं। और इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर संशोधन का कार्य होता है। यह पूर्वानुमान सही है या नहीं इसका सत्यापन करके कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययनके लिये निम्न परिकल्पनाओं को शोध का आधार बनाया जायेगा।

- 1) अन्य महिलाओं की तुलना में दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की समस्याएँ ज्यादा हैं।

- 2) दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की सामाजिक स्थिति के कारण उनपर अत्याचार होते रहे हैं।
- 3) कार्यस्थलों पर दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं से भेदभाव पूर्ण व्यवहार हो रहा है।
- 4) दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की बौद्धिक क्षमताओं को कम आकां जा रहा है।

1.5 शोध प्रविधि

समस्या का निर्माण करने के पश्चात परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। उसके बाद समस्या से संबंधित सामग्री एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ होता है। इसके लिए प्रस्तुत शोध प्रबंध में निदर्शन प्रविधि तथा तथ्य संकलन प्रविधि के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितियक स्रोत का भी उपयोग किया जाएगा।

अ) निदर्शन प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य करने के लिए वर्धा शहर जिला-वर्धा (महाराष्ट्र) की कुल 50 दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं को चयनीत किया जाएगा जिसमें 25 दलित कामकाजी महिलायें तथा 25 आदिवासी कामकाजी महिलायें हैं। इनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया जाएगा।

ब) तथ्य संकलन प्रविधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितियक दोनों प्रविधियों का उपयोग किया जाएगा।

